(b) if so, whether it is also a fact that a representative of one of the six recognised associations of employees has been made a member thereof;

(c) if so, the rationale of such a discriminating action of the Sangathan;

(d) whether any protest has been made against this action; and

(e) if so, the reaction of the Sangathan thereto?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) to (e) There is no discrimination in nominating one teacher representative which is considered adequate for such a Committee. However, persons who were currently Presidents of the different associations have been nominated on appropriate forums namely the Kendriya Vidyalaya Sangathan and its Board of Governors. The Joint Consultative Machinery has also been activated. The suggestion of the General Secretary, All India Kendriya Vidyalaya Teachers' Association, in his letter dated 3.6.92, to grant one seat each to the remaining two teachers' associations, cannot be accepted.

Resumption of Agitation by AIKVTA

314. SHRI SARADA MOHANTY:
DR. SANJAYA SINH:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that AIKVTA have decided to resume their suspended agitation from 14th July, 1992;

(b) if so, the details of their demands;

(c) the stand of the Sangathan on each of these demands; and

(d) what eortffs have been made by Kendriya Vidyalaya Sangathan to avoid the untoward situation and the result thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) The General Secretary, All India Kendriya Vidyalaya Teachers' Association (AIKVTA) vide his letter dated 17-6-92 has intimated that AIKVTA have decided to resume from 14th July, 1992 its phased agitation.

(b) and (c) The AIKVTA has raised various issues from time to time. The positon in respect of each demand is given in Annexure [*See* Appendix CLXIV, Annexure No. 67]

(d) The Presidents of the different employees' associations including All India Kendriya Vidyalaya Teachers' Association have for the first time now been included in the Sangthan and its Board of Governors and Joint Consultative Machinery has also been activated. The Government is always willing to discuss with employees any genuine grievances so that reasonsable solutions could be arrived at.

Reddy Committee on education policy

315. SHRI P. UPENDRA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 625 given in Rajya Sabha on the 28th February, 1992 and state:

(a) whether Government have finalized its views on the recommendations of the Reddy Committee on Education Policy; and

(b) if so, what steps have been taken to implement the recommendations?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) and (b) The Report of the Central Advisory Board of Education (CABE) Committee on Policy (Janardhana Reddy Committee was considered by the CABE in its meeting held on 5th and 6th May, 1992. On the basis of the recommendations of the CABE certain modifications were effected in the National Policy on Education (NPE), 1986. The revised Policy Formulations were laid on the table of the House on 7th May, 1992.

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन

316. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम में व्यापक संशोधन करने के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करने के लिए विधेयक कब तक पुनःस्थापित किये जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) सरकार ने मई, 1990 में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम 1915 को संशोधित करने के लिए कानून का प्रारूप तैयार करने के लिए एक प्रारूपण समिति गठित की थी। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के अनुरोध पर प्रारूपण समिति की रिपोर्ट दिसम्बर, 1991 में विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् को उसके विचारार्थ भेजी गई थी। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधित करने के लिए कानून तैयार करने के संबंध में आगे की कार्रवाई कार्यकारी परिषद् के विचार उपलब्ध होने के पश्चात् ही संभव हो सकेगी।

मध्य प्रदेश को रियायती दर पर कागज की आपूर्ति

317. **श्री लखीराम अग्रवाल :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुस्तकों के मुद्रण के लिये रियायती दरों पर कागज उपलब्ध कराये जाने संबंधी मध्य प्रदेश सरकार का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के शैक्षिक क्षेत्र को मुद्रण का सफेद कागज, रियायती दरों पर दिए जाने की एक योजना, 31 मार्च, 1990 तक चल रही थी। मार्च, 1990 में, इस योजना को समाप्त कर दिये जाने के बाद, मध्य प्रदेश राज्य सरकार से, पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण के लिए रियायती दरों पर मुद्रण का सफेद कागज उपलब्ध कराए जाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ था। इस योजना को बंद कर दिए जाने के बाद, मध्य प्रदेश राज्य को कागज आवंटित नहीं किया जा सका।

देश में नवोदय विद्यालय

318. **श्री राम जेठमलानी :**

श्री रणजीत सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री 28 फरवरी, 1992 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न सं० 624 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार 1986 में घोषित शिक्षा नीति के अन्तर्गत देश में नवोदय विद्यालय स्थापित करने के लिए कृत संकल्प है ;